1105/rajinder

RS 11.05 Shl. 18.12.2023

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 21

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो अगर कहीं पर कोई नई सड़क बनवानी होती है तो उसके लिए कई-कई साल तक अखबारों के माध्यम से बात उठानी पड़ती है कि सड़क टूटी पड़ी है और लोग परेशान हैं। उसके बाद जब साल दो साल के बाद किसी सड़क के बनने का नम्बर आता है तो सड़क बनते-बनते ही सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि बरसात के कारण कई जगह सड़क में गढ्डे पड़ गये जिनका पैच वर्क करवा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि यह सड़क तो बनते-बनते ही टूट गई थी। उस समय जब केशव कालोनी, रायपुररानी के कुछ दुकानदार आपके पास आये और उन्होंने यह कहा कि वहां पर जो नाला बन रहा है वह गलत बन रहा है उनके द्वारा उस नाले का बहुत विरोध किया गया लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी आवाज की सुनवाई नहीं की गई और आज भी उस नाले की स्थिति वैसी की वैसी है। बरसात के मौसम में उनका बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है। अगर अब भी बरसात पड़ेगी तो अब भी पहले की ही तरह पानी भर जायेगा। चाहे केशव कालोनी हो, कशाल वाला मंदिर हो और चाहे आईडिया टॉवर कॉलोनी हो वहां के सभी लोग आज भी उस नाले से परेशान हैं। जब भी बरसात पड़ती है तो तहसील के सामने दो-दो फुट पानी इक्ट्ठा हो जाता है। वहां पर डिवाइडर टूटे पड़े हैं। शुक्रवार को जब मेरा क्वैश्चन लगा तभी वीरवार को वहां पर पैच वर्क का काम किया गया। वहां पर अगर गांव गढ़ी से लेकर रायपुररानी तक देखा जाये तो कितने पैच वर्क उसमें हुए हैं। वहां पर नाले टूटे पड़े हैं। जो पांच-पांच फुट का फुटपाथ बनाया गया था वह भी टूटा पड़ा है। फुटपाथ तो कहीं-कहीं पर दब भी गया है। फुटपाथ का कहीं पर भी पता नहीं चलता। पी.डब्ल्यू.डी. के स्तर पर उस सड़क में यूज किये गये मैटीरियल की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये। आज वहां पर लोग इस सड़क के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके डर से अकेली केशव कॉलोनी में से ही दो-तीन परिवार अपने मकान बेचकर पलायन करके चले गए हैं। मेरी बार-बार यही रिक्वैस्ट है कि इस सड़क में यूज किए गए मैटीरियल की पी.डब्ल्यू.डी. के स्तर पर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये। यह स्टेट हाईवे का मामला है। यह रोड बड़ी मुश्किल से बनी है। बनते-बनते ही यह सड़क टूटनी शुरू हो गई। वहां पर जगह-जगह नाले टूटे पड़े हैं। इसकी जांच करवाई जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क की बात कही थी वह मौली से भूरेवाला सड़क थी। इस सड़क की टोटल लम्बाई 13.4 किलोमीटर है। इस सड़क की date of completion 30.11.2022 थी और 24.11.2022 को इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। इस सड़क के निर्माण में कोई डिले नहीं हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने बोला है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क टूट गई। माननीय सदस्य की पूरी कांस्टीच्युएंसी में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इस बार जुलाई में हैवी मानसून के कारण रोड डेमैज न हुई हो केवल पी.डब्ल्यू.डी. और स्टेट हाईवेज की बात ही नहीं है, शिमला जाने वाला नैशनल हाईवे जो इतने बड़े कंक्रीट वॉल के साथ गार्डिड था उसको भी पंचकूला और कालका के बीच में पानी का बहाव काटकर ले गया। जहां इस सड़क में पानी के बहाव से नुक्सान हुआ था वह टोटल रिपेयर कर दिया गया था। यह सड़क डिफैक्ट लॉयबिलिटी पीरियड के अंदर होने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बल्कि उस कांट्रैक्टर ने ही इस सड़क की रिपेयर की है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक नहीं 1200 से ऊपर गांवों को जोड़ने या टच करने वाली छोटी-बड़ी सड़कों का नुक्सान हुआ है और हमने प्रॉयरिटी के तौर पर उन सभी सड़कों को इमीडियेट रिपेयर में डाला ताकि संसाधनों की मूवमैंट में कोई कमी न आये। फिर भी माननीय सदस्य यदि कहते हैं कि कोई स्पैसिफिक कॉलोनी का कोई स्पैसिफिक नाला बनाया जाना है तो इस बारे मेरा यही कहना है कि नाला बनवाना और नाला मेनटेन करना कई जगह एम.सीज. का काम है और कई जगह पंचायती राज का काम है। हमारी व्यवस्था सिर्फ इतनी होती है कि इनीशियली तौर पर जब सड़क बनती है तो वहां प्रॉविजन डाली जाये। लोग अपनी व्यवस्था के लिए भी मिलते हैं क्योंकि दुकान के पास नाला ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। उसकी समयानुसार हम रिमॉडलिंग करते रहते हैं।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब नाला बनाया जा रहा था उस समय वहां के लोग पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों के पास मिलने के लिए गए उस समय अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि हम उसको ठीक कर देंगे लेकिन आज भी वह नाला ठीक नहीं हुआ है। आज भी वहां के लोग बरसात से डरते हैं कि पता नहीं कब बरसात हो जाये और उनके घरों और दुकानों में पानी भर जाये। इससे वहां पर एक बहुत बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहां पर नाले टूटे पड़े हैं। परसों ही वहां पैच वर्क का काम शुरू किया गया है। जब विधान सभा में मेरा सवाल लगा उसके बाद ही वहां पर काम शुरू किया गया। ये मेरे पास परसों की फोटोज हैं। मेरा बार-बार यही कहना है कि इस नाले को जल्दी से जल्दी ठीक

करवाया जाये क्योंकि पिछली बार लोगों के घरों और दुकानों में पानी जाने के कारण फ्रिज खराब हो गये, गेहूं खराब हो गई और कपड़े खराब हो गये। मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये।

1110/Om Parkash

18.12.2023 Rana/Rajesh 11.10

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल एक सड़क से शुरू हुआ था और अब नाला बनाने पर आ गया है। मैं इसकी इन्कवायरी करवा लेता हूं और संबंधित विभाग चाहे वह रूरल डिवैल्पमैंट हो या अर्बन लोकल बॉडीज का एरिया पड़ता हो उनसे हम पानी की एक्सैस के लिए लैंड उपलब्ध करवाने के लिए कहेंगे। आपने स्वयं देखा है कि एन.एच.ए.आई. जैसी ऐजेन्सी को भी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि रेन वाटर ड्रेन तो हाइवे के साथ-साथ बन जाती है लेकिन उससे आगे एक्सेसिबिलिटी के लिए लैंड नहीं मिलती है जिसके कारण आगे पानी नहीं निकल पाता है। इसके बावजूद भी मैं इसकी इन्कवायरी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: उप-मुख्यमंत्री जी, वहां पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आप एक नाला बनवा दीजिए यह समस्या समाप्त हो जायेगी। वह तो सड़क के साथ ही नाला बनना है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 22

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग 20 हजार शिक्षक भर्ती किये थे। उस समय जल्दी में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी इसलिए अतिथि अध्यापकों की भर्ती की गई। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में लगभग 12746 अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल के कार्यकाल के बाद भी अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया गया। जहां तक मंत्री जी के जवाब की बात है तो उसमें यह लिखा हुआ है कि ये अतिथि अध्यापक 58 साल यानी सेवा निवृति की तिथि तक कार्यरत रहेंगे। जहां तक अतिथि अध्यापकों और नियमित अध्यापकों की सैलरी की बात है तो जे.बी.टी. गैस्ट टीचर्स को 35400/- रुपये का स्लैब दिया जाता है जबकि नियमित जे.बी.टी. टीचर्स को 55 हजार रुपये का स्लैब मिलता है। इसी प्रकार से टी.जी.टी. की बात की जाये तो गैस्ट टीचर्स को 39900/- तथा नियमित टीचर्स को 65 हजार रुपये का स्लैब मिलता है। अगर पी.जी.टी. की बात की जाये तो इसमें भी गैस्ट टीचर्स को 47600/- रुपये तथा नियमित टीचर्स को 70 हजार रुपये का स्लैब मिलता है जबकि वे भी पूरे समय तक ड्यूटी देते हैं। उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है? उनको सर्विस करते हुए 18 साल का समय हो गया है इसलिए उनको उनके सभी अधिकार मिलने चाहिएं। जहां तक उनकी ट्रांसफर पॉलिसी की बात है तो इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। अध्यापकों के साथ ही अतिथि अध्यापकों की भी 5 साल के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें गैस्ट टीचर्स को भी ठहराव होना चाहिए तथा गैस्ट टीचर्स को भी यैस और नो का ऑप्शन होना चाहिए। जहां पर पति-पत्नी गैस्ट टीचर्स हैं उनको भी नियमित टीचर्स की तरह अतिरिक्त अंक मिलने चाहिएं। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में जब गैस्ट टीचर्स की भर्ती की गई थी तब वह पीरियड के हिसाब से भर्ती की गई थी लेकिन उसके बाद उनको रेगुलर तनख्वाह दी जाने लगी। उसके बाद 12.03.2019 को हरियाणा स्टेट गैस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट, 2019 लागू किया गया। यह उन्हीं की डिमांड थी और यह उनके साथ विचार-विमर्श करके लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत गैस्ट टीचर्स 58 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे यानी उनको बीच में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हम हटायेंगे। इस एक्ट में गैस्ट टीचर्स की सर्विस को रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस एक्ट के तहत गैस्ट टीचर्स को दिये जाने वाले मासिक मानदेय पर रेगुलर टीचर्स को दिये जाने वाले डी.ए. के अनुरूप वर्ष में दो बार जनवरी तथा जुलाई में महंगाई भत्ता दिया जाता है।